1	2	3	4	5
24.	पश्चिम बंगाल . .	(+) 3.8	(+) 3.7	(+) 0.1
25.	सिक्किम . .	(+) 3.7	(+) 1.2	(+) 3.4
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	(+) 5.6	(+)26.3	—
2.	चण्डीगढ़ . .	(+) 3.2	(+) 6.3	(+) 8.8
3.	दादर व नगर हवेली .	—	—	(+)33.3
4.	दिल्ली . . .	—	(+) 1.3	(+) 3.5
5.	लक्षद्वीप . .	—	—	—
6.	पाण्डिचेरी . .	—	—	—
	अखिल भारत :	(+) 4.9	(+) 3.2	(+) 3.5

किसानों की संख्या में कमी

2838. **श्री आस मोहम्मद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की संख्या में कमी आई है जबकि कृषि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एल० कृष्ण कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र में कमी

2839. **श्री आस मोहम्मद:** क्या कृषि मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950 और वर्ष 1990 में देश में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र कितना-कितना था ;

(ग) क्या सरकार भूमि की उपलब्धता में लगातार आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए भावी विकास योजनाओं के लिए भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यापक अध्ययन कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1951 में भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 0.9 हेक्टेयर थी जो घटकर 1991 में 0.4 रह गई। ये आंकड़े 1951 तथा 1991 की गणना पर आधारित हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूप रेखा तथा देश के भू-संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और प्रबन्ध

के लिए कार्रवाई के मुद्दे तैयार किए हैं। भू-उपयोग नीति की रूप-रेखा को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भू-उपयोग और पनधरा विकास परिषद की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था और इसे कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने आंचलिक आधार पर भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध के लिये संदर्शी योजना तैयार करने का, कार्य संबंधित जोनों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी अंचलों में जाने-माने संस्थानों/परामर्शदाताओं को सौंप दिया है। पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अंचलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शेष 3 जोनों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी से अन्ततः भूमि पर दबाव कम हो जायेगा जिसके लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

उर्वरकों की खपत में कमी

2840. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इनकी खपत में कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उर्वरकों की खपत में कमी आने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार देश के सीमांत और छोटे किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) अगस्त 1992 में नियंत्रणरहित फास्फेटयुक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण वर्ष 1992–93 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 121.55 लाख मीटरी टन तक ही रही जो कि 1991–92 के दौरान हुई 127.28 लाख मीटरी टन की खपत से लगभग 4.5 प्रतिशत कम है। 1993–94 के दौरान इनकी खपत 123.66 लाख मीटरी टन तक हुई थी जो कि 1992–93 की खपत से 1.7 प्रतिशत अधिक है। 1994–95 के दौरान पोषक तत्वों की खपत लगभग 138.30 मीटरी टन होने की संभावना है।

(ग) उर्वरकों की खपत खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। खाद्यान्न उत्पादन 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 168.4 मिलियन मीटरी टन, 179.5 मिलियन मीटरी टन और 182 मिलियन मीटरी टन हुआ था। 1994–95 में यही स्तर बरकरार रखने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को स्वदेशी डाई अमोनियम फास्फेट और म्यूरिएट आफ पोटाश की बिक्री पर 1000 रुपये प्रति मीटरी टन की रियायत और स्वदेशी मिश्रणों की बिक्री पर आनुपातिक रियायत और स्वदेशी सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री पर 340 रुपये प्रति मीटरी टन की रियायत दे रही है।

उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

2841. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गड़सा, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश स्थित उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय